बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 89 ● नई दिल्ली ● वीररवार 15 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद के घर में लगी आग, मचा हड़कंप, घटनास्थल पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियां

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में आज सुबह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास पर आग लगने की एक घटना सामने आई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू की। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और आग लगने के कारणों की गहन जांच में जुटी है।अग्निशमन विभाग को सुबह करीब 8:05 बजे मदर डिसेंट रोड स्थित एक कोठी नंबर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग ने तत्परता दिखाते हुए अपनी तीन गाड़ियां तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दीं।

सेना प्रमुख द्विवेदी ने गणतंत्र दिवस शिविर का किया दौरा, एनसीसी कैडेटों से की बातचीत

नई दिल्ली ।

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को दिल्ली छावनी के कारियाप्पा परेड कैंप में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा किया। इस दौरान, सीओएएस ने राष्ट्रीय आयोजन के लिए चयनित कैडेटों से बातचीत की। शिविर के दौरे के अलावा, जनरल द्विवेदी और एडब्लूडब्ल्यूए की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी ने आर्मी हाउस में कैडेटों का स्वागत किया। कैडेटों से बातचीत करते हुए सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

इसके साथ ही अनुशासन, दृढ़ता, कड़ी मेहनत और नेतृत्व को चरित्र और उत्कृष्टता के आधार स्तंभ बताया।

जेन-जी को शक्ति का भंडार- सेना प्रमुख द्विवेदी

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हाल की घटनाओं ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय युवा क्या करने में सक्षम हैं। आप जेनरेशन जेड की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी आबादी हैं। हमारे युवा शक्ति का भंडार हैं, जिसे अनुशासन, उद्देश्य और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ सही दिशा में ले जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत के संकल्प और संयम का एक निर्णायक प्रदर्शन था, जो हमारे सशस्त्र बलों और युवाओं की नैतिक शक्ति और पेशेवर उत्कृष्टता का प्रतिबिंब था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में 75,000 से अधिक एनसीसी कैडेटों ने स्वेच्छा से नागरिक सुरक्षा, अस्पताल प्रबंधन, आपदा राहत और सामुदायिक सेवाओं में अथक परिश्रम किया। 2025 में, 10 एनसीसी कैडेटों, जिनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां थीं, जिनकी औसत आयु मात्र 19 वर्ष थी, ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। मुझे उनसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

जनरल द्विवेदी ने अपने अनुभव साझा किया

जनरल द्विवेदी ने चयनित मेधावी कैडेटों को सम्मानित किया। वहीं, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें भारत के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा-इस संवाद ने कैडेटों को वीरता पुरस्कार विजेताओं और खिलाड़ियों से मिलने का अवसर भी प्रदान किया, जिनमें सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट संजय कुमार, ओलंपियन ह्वेकाटो सेमा और ओलंपियन जैस्मिनी शामिल हैं।

30 दिसंबर से शुरू होआ गणतंत्र दिवस शिविर

राष्ट्रीय कैडेट कोर का एक महीने तक चलने वाला गणतंत्र दिवस शिविर 30 दिसंबर को कारियाप्पा परेड शिविर में पारंपरिक सर्व धाम पूजा के साथ शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, शिविर में कई अंतर-निदेशालय प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ कैडेट प्रतियोगिता, लघु शस्त्र फायरिंग, ध्वज क्षेत्र डिजाइनिंग और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मार्चिंग टुकड़ी का चयन।इस वर्ष के आरडीसी में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी दर्ज की गई है, जिसमें 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों से 898 महिला कैडेटों सहित 2,406 कैडेट शामिल हुए हैं। युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी भाग ले रहे हैं, जिससे इसमें एक अंतरराष्ट्रीय आयाम जुड़ गया है।

एनसीसी के महानिदेशक ने इससे पहले संबोधन किया था

इससे पहले 30 दिसंबर को, एनसीसी के महानिदेशक और लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कैडेटों को संबोधित किया। उन्हें प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कैडेटों से राष्ट्र सर्वोपरि की सच्ची भावना से प्रेरित होकर, धर्म, भाषा और जाति की बाधाओं को पार करते हुए, चरित्र, सत्यनिष्ठा, निस्वार्थ सेवा, भाईचारा और टीम वर्क जैसे सर्वोच्च गुणों का प्रदर्शन करने का आग्रह किया।एकता और अनुशासन के अपने आदर्श वाक्य को कायम रखते हुए, गणतंत्र दिवस शिविर देश भर से एनसीसी कैडेटों को एक साथ लाता है और उन्हें प्रशिक्षण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करता है, साथ ही कैडेटों में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व की गहरी भावना पैदा करता है।

दिल्लीवासियों को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की मिली सौगात, संख्या बढ़कर 319 हुई

नई दिल्ली ।

दिल्ली में आम लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. राजधानी में आज (14 जनवरी) से 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू कर दिए गए हैं.

इन आरोग्य मंदिरों के शुरू होने से खास तौर पर गरीब, मध्यम वर्ग और झुग्गी-बस्ती में रहने वाले लोगों को अपने घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के नांगल राया इलाके में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली के हर नागरिक को समय पर और मुफ्त इलाज मिले. वहीं, दिल्ली सरकार के अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायक भी अपनी-अपनी विधानसभाओं में आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए. खास बात यह रही कि सभी 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन एक ही समय पर रिमोट दबाकर सीएम द्वारा किया गया. नांगल राया स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जायजा लिया. यहां पर मरीजों के लिए साफ-सुथरी व्यवस्था, डॉक्टरों की मौजूदगी और जरूरी दवाओं की उपलब्धता देखने को मिली. स्थानीय लोगों ने बताया कि अब छोटी-मोटी बीमारी के लिए उन्हें बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बुखार, खांसी, सर्दी, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों का इलाज अब पास में ही हो सकेगा.

दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या बढ़कर हुई 319

दिल्ली में इससे पहले 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले से संचालित थे. 81 नए केंद्र जुड़ने के बाद अब राजधानी में इनकी कुल संख्या बढ़कर 319 हो गई है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में 1100 से यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का है, ताकि हर इलाके में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके.

आरोग्य मंदिरों में लोगों का होगा मुफ्त इलाज

सरकार के अनुसार, इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मुफ्त इलाज, जरूरी दवाएं और डायग्नोस्टिक जांच की सुविधा दी जाएगी. इनमें ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी जांच जैसी बुनियादी जांच शामिल है. साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. साथ ही समय-समय पर सीनियर और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी इन केन्द्रों पर पहुंचकर मरीजों का इलाज करेंगे.

अब जनता को समय पर मिल सकेगा इलाज

गौरतलब है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू किए जा रहे हैं, जिसका मकसद दिल्ली में मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना है. दिल्ली में इन केंद्रों के विस्तार से सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा और आम जनता को समय पर इलाज मिल सकेगा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, भारतीय राजनीति में अलगाववाद की Case Study हैं

नई दिल्ली । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल भारतीय राजनीति में अलगाववाद का सटीक उदाहरण और जीता-जागता सबूत हैं। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुरु प्रकाश ने कांग्रेस और विपक्षी नेतृत्व पर राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषाई कट्टरता का सहारा लेने का आरोप लगाया, जो उनके अनुसार राष्ट्रीय एकता, शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। भाजपा प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण राय दर राय बदलता रहता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें चुनावी लाभ किससे मिलेगा। गुरु प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी का इतिहास ऐसा है कि जब वे बिहार जाते हैं, तो जाति के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, और जब वे तमिलनाडु जाते हैं, तो तमिल पहचान के नाम पर नकारात्मक राजनीति करते हैं। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अलगाववाद का सटीक उदाहरण और केस स्टडी हैं। उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तमिल मुद्दों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पर राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए गुरु प्रकाश ने कहा कि क्या राहुल गांधी हमें कोई प्रमाण पत्र देंगे? आप कोई प्रमाणन प्राधिकरण नहीं हैं जो तमिल मुद्दों, शाश्वत तमिल सभ्यतागत विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, आपको यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि हम तमिल आवाज को दबाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की सभ्यतागत भावना के अभिन्न अंग के रूप में तमिल संस्कृति, भाषा और पहचान को लगातार महत्व दिया है और बढ़ावा दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आप राजनीति की बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल सभ्यतागत विरासत के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंचों पर भी तमिल पहचान के प्रति निरंतर सम्मान प्रदर्शित किया है।

घर से 400 मीटर दूर आरडब्लूएए अध्यक्ष का मर्डर, सीएम रेखा परिवार से मिली तक नहीं; आप नेता हत्याकांड पर बोले सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली में आरडब्लूएए अध्यक्ष व आप नेता रचना यादव की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आरडब्लूएए अध्यक्ष रचना यादव की घर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि हत्यारे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई लचर है। सौरभ भारद्वाज ने इस घटना को लेकर दुख जताया है और भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हत्यारे कब गिरफ्तार किए जाएंगे? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गईं। कहा कि रेखा गुप्ता उसी वार्ड से पार्षद थीं, अब उसी इलाके से एमएलए हैं।

बदमाश ने पीछे से नाम बोला, फिर मार दी गोली

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जब महिला घर की गली में पहुंची, तो पहले से गली में खड़ा बदमाश पीछे-पीछे गया। महिला का नाम लिया, जैसे ही महिला ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, बदमाश ने सिर में गोली मार दी। आसपास गली में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले आरोपी फरार हो गए।

रचना यादव को पति हत्याकांड में देनी थी गवाही

दरअसल, वर्ष 2023 में रंजिश के कारण रचना के पति की हत्या कर दी गई थी। बेटियों का आरोप है कि इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी का सुप्रीम कोर्ट से बेल रद्द होने पर उनकी मां की हत्या कर दी गई। उनकी मां इस केस में मुख्य गवाह थी। जल्द ही उनकी मां और दो अन्य लोगों की इस केस में गवाही होनी थी।

कोर्ट जाते समय धमकी

बेटी कनिका ने बताया कि जब मां कोर्ट में तारीख पर जा रही थीं, उस समय भी उनका पीछा किया गया था। उन्हें धमकाया गया था। जब से उनकी मां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में शामिल होती थीं, उनकी मां हर समय डरी रहती थी। इधर धमकी मिलने के बाद भी वह काफी अलर्ट रहती थीं। बदमाश वारदात को अंजाम देने से एक घंटे पहले भी क्षेत्र में रेकी करते देखे गए हैं।

महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में एक आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अभी सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा और आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। भारत में साधुओं के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि, 20 सितंबर, 2021 को इलाहाबाद के बाघंबरी मठ में फांसी पर लटके मिले थे। सीबीआई ने नवंबर 2021 में दायर अपनी चार्जशीट में कहा था कि गिरि अपने अलग हो चुके शिष्य आनंद गिरि, पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के चलते गंभीर मानसिक तनाव में थे कि उन्होंने समाज की नजरों में बदनामी और अपमान से बचने के लिए अपनी जान दे दी। सोमवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 14 अक्टूबर, 2025 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए आद्या प्रसाद तिवारी को जमानत दे दी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आद्या प्रसाद तिवारी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा, ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है। वैसे भी, अपीलकर्ता मुख्य आरोपी नहीं लगता है। इसे देखते हुए, हमारी राय है कि ट्रायल के दौरान अपीलकर्ता को और हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता 22 सितंबर, 2021 से हिरासत में है, और ट्रायल के दौरान उसे और हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। इस मामले में एफआईआर 21 सितंबर, 2021 को प्रयागराज जिले के जॉन्स टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। तिवारी को शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 18 नवंबर, 2021 को दायर की गई चार्जशीट में हत्या (धारा 302) और आपराधिक साजिश (धारा 120) के आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ट्रायल कोर्ट को यह आजादी दी कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो वह जमानत रद्द कर सकती है। चार्जशीट में इलाहाबाद के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी पर आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है।

पुस्तक मेले में जाइए, बच्चों के लिए हिंदी किताबें लाइए

अगर आपको हिन्दी से प्रेम है तो कुछ ऐसा कीजिए, जिससे बच्चों को हिन्दी भाषा का चस्का लग जाए। उन्हें हिन्दी बोलने ही नहीं, पढ़ने और लिखने में रस आना शुरू हो जाए। उनके लिए हिन्दी सिर्फ गपियाने और गलियाने की ही नहीं, बल्कि अपने आपको और देश-दुनिया को समझने-समझाने की भाषा बन जाए। उन्हें हिंदी बोलने में झेंप न आए। बिना वजह टूटी-फूटी अंग्रेजी न बोलें। यह तब होगा जब हिन्दी में बच्चों के लिए अच्छा साहित्य उपलब्ध हो। और यह तब होगा, जब हिंदी के बेहतरीन लेखक बच्चों के लिए लिखेंगे। अंग्रेजी में बाल साहित्य की महिमा है। हैरी पॉटर लिखने वाली जे.के. राउलिंग या फिर ग्रफलो की रचयिता जूलिया डोनाल्डसन दुनिया भर में शोहरत पाती है। बांग्ला, मराठी और मलयालम में भी बाल लेखन की परंपरा रही है। लेकिन हिंदी के बाल साहित्य के लेखक को तो उसकी गली में भी कोई नहीं पूछता। साहित्यकारों की दुनिया में भी छोटे बच्चों के लिए लेखन को छोटा लेखन समझा जाता है। नतीजतन, हिंदी के बाल साहित्य में कई दशकों तक ठहराव रहा। आधुनिकता का मतलब समझा जाता है अंग्रेजी। इसलिए बच्चों को अंग्रेजी से अनूदित ऐसी कहानियां पढ़ाई जाती है, जिनके संदर्भ, कथानक और पात्रों का भारतीय बच्चों से कोई संबंध नहीं। अपने 'स्व' से अलगाव से शुरू होता है एक औसत हिंदुस्तानी का हीनता बोध, जो अक्सर फूहड़ और आक्रामक स्वरूप लेता है।लेकिन अच्छी खबर यह है कि हालात बदल रहे हैं। पिछले 10-15 बरस में भारत के बाल साहित्य का कायाकल्प हो गया है। शुरुआत अंग्रेजी से हुई, जहां सुनहरी बालों और नीली आंखों वाले गोरे बच्चों की बजाय हमारे सांवले बच्चों के सलोने या फिर खट्टे-मीठे जीवन पर कहानियां लिखी जाने लगीं। एक जमाने में भारत सरकार के नैशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने भी यह शुरुआत की थी लेकिन फिर वह सरकारी तंत्र में कहीं दब गई। पिछले कुछ साल से कुछ संस्थाओं के प्रयास से हिंदी में बदलाव की बयार बह रही है। दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में आप हिंदी के नए बाल साहित्य की झलक देख सकते हैं। यूं तो मेले के 6 नंबर हॉल में पेश बाल साहित्य में अंग्रेजी और अंग्रेजी से अनूदित साहित्य का बोलबाला है लेकिन अगर आप उस चमक-धमक में 'इकतारा' और 'एकलव्य' की सादी स्टाल को ढूंढ पाएं तो आपको हिंदी के बाल साहित्य की नई चमक दिखाई देगी। 'इकतारा' के जुगनू प्रकाशन ने निस्संदेह हिंदी के बाल साहित्य के अंधकार में जुगनू की तरह रौशनी फैलाई है। इस एक स्टाल से आप बच्चों के लिए एक शानदार लाइब्रेरी बना सकते हैं-नन्हे बच्चों के लिए शब्दरहित चित्र पुस्तकें, नाना प्रकार और आकार की कहानी और कविता की पुस्तकें, पोस्टर, कैलेंडर, कविता कार्ड, किशोर अवस्था के लिए उपन्यास और बहुत कुछ। उनकी दोनों बाल पत्रिकाएं-बच्चों के लिए 'प्लूटो' और किशोरों के लिए 'साइकिल' पढ़कर आप खुद भी लुत्फ ले सकते हैं। इसी तरह एकलव्य की स्टाल पर आपको हिंदी के बाल साहित्य का 'पिटारा' मिलेगा। ग्रामीण बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण से शुरू हुई यह संस्था बच्चों के लिए कथा साहित्य भी प्रकाशित कर रही है, नए प्रयोग कर रही है, देश के हर कोने और समुदाय के बच्चों के अनुभव को समेट रही है। ज्ञानवर्धक सामग्री और मनोरंजन से भरपूर उनकी बाल विज्ञान पत्रिका 'चकमक' किसी भी स्कूल ले लिए अनिवार्य होनी चाहिए। 'मुस्कान' का अपना स्टाल नहीं है लेकिन अंतिम पायदान पर बैठे कूड़ा बीन रहे बच्चों की आपबीती आपको उनकी किताबों में दिखेगी। प्रथम बुक्स में भी आपको भारतीय संदर्भ में बसी हिंदी की सुंदर और सुसज्जित किताबें मिलेंगी। हालांकि उनमें से ज्यादातर अनूदित हैं लेकिन अनुवाद अच्छा होने के कारण खटकता नहीं। अगर आप नैशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में उनकी पुरानी किताबें खोजेंगे तो आपको कुछ काम की किताबें मिल सकती हैं। हिंदी के बड़े व्यावसायिक प्रकाशकों को अभी तक बाल साहित्य में दिलचस्पी नहीं जगी है। अच्छी खबर यह भी है इधर इकादी के नामचीन लेखकों ने भी बच्चों के लिए लिखा है। गीतकार और शायर गुलजार तो पिछले कई दशकों से बच्चों के लिए लिख रहे हैं। जुगनू प्रकाशन उनकी 14 नई कहानियों का एक सैट लेकर आया है जिसमें एलेन शॉ के चित्रों ने जान डाल दी है। हर किताब का अपना अलग अंदाज है और अलग पाठक वर्ग है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी के मूर्धन्य लेखक विनोद कुमार शुक्ल, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में बच्चों के लिए कविताएं, कहानियां और उपन्यास लिखे। इन दिनों हिंदी के स्थापित लेखक और साहित्यकार अरुण प्रकाश, प्रियंवद, राजेश जोशी, असगर वजाहत, प्रयाग शुक्ल, कृष्ण कुमार, उदयन वाजपेयी और लाल्टू भी बच्चों के लिए लिख रहे हैं। साथ ही बच्चों के लिए लिखने वाले कुछ लेखक भी अब धीरे-धीरे दुनिया की नजर में आने लगे हैं। इनमें मेरे प्रिय लेखक हैं सुशील शुक्ल, जिनकी सीधी-सरल कविताएं गुदगुदाने के साथ दिमाग की खिड़की भी खोल देती हैं। बाल लेखन के सितारों में शशि सबलोक, प्रभात, चन्दन यादव और वरुण ग्रोवर के नाम जोड़े जा सकते हैं। बच्चों की किताबों की जान है चित्रांकन। अब तापोशी घोषाल, प्रशांत सोनी, राजीव आइपे सरीखे कलाकारों की एक जमात उभर रही है, जो बच्चों की किताबों को आकर्षक बना रही है। आप भी इस पुस्तक मेले में जाइए और बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में हिंदी किताबें देना शुरू कीजिए। एक सरकारी हिंदी दिवस पर उसकी पूजा करने से हिंदी का उत्थान होने वाला नहीं है। अगर आप मन से अपनी भाषा की समृद्धि चाहते हैं तो हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के झूठे दावे से बाज आइए। राजभाषा की हैसियत से बाकी भारतीय भाषाओं पर धौंसपट्टी मत कीजिए। हिंदी-उर्दू के झूठे झगड़े को बंद कीजिए। बच्चों को मातृभाषा के उपदेश न दीजिए।

आसमान में उड़ती 'चांदी'

भारत में चांदी गरीब आदमी के आभूषणों की बहुमूल्य धातु समझी जाती है परन्तु अब इसके दामों में पंख लग गये हैं और यह सामान्य नागरिक की पहुंच से भी बाहर मानी जाने लगी है। दूसरी तरफ सोने के दामों में भी पर लगे हुए हैं और इसके दाम भी हवा में गोते लगाते हुए लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। सोना जहां डेढ़ लाख प्रति दस ग्राम के स्तर को छूने की तरफ बढ़ रहा है, वहीं चांदी भी अब ढाई लाख रुपए प्रति किलो से भी ऊपर दो लाख 65 हजार रुपये प्रति किलो की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है।

चांदी के दामों में पिछले वर्ष 2025 के दौरान डेढ़ गुना से भी ज्यादा 160 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। बीते कल दिन ही इसके दामों में 15 हजार रुपये किलो की वृद्धि दर्ज हुई। इसकी मूल वजह यह मानी जा रही है कि जहां एक तरफ चांदी की मांग में औद्योगिक क्षेत्र से वृद्धि हो रही है वहीं इसकी सप्लाई में वृद्धि दर्ज नहीं हो रही है और साथ ही विश्व के अत्यधिक उतार-चढ़ाव भरे माहौल में यह सुरक्षित निवेश का बढ़ता हुआ साधन भी मानी जाने लगी है। सोने के दामों में वृद्धि की वजह दूसरी है क्योंकि बदलती विश्व व्यवस्था में इसे सुरक्षित निवेश का सुरक्षित साधन माना जा रहा है और अमेरिकी मुद्रा डॉलर के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ढीलेपन की वजह से स्वर्ण में निवेश अत्यधिक मोहक होता जा रहा है। इसके बावजूद भारत में सोने-चांदी की घरेलू मांग में भी कमी दर्ज नहीं हो रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि दीपावली पर्व के अवसर पर भारत में चांदी की मांग में जोरदार वृद्धि होती है मगर इस बार बीती दीपावली पर चांदी के दाम इतने महंगे रहे कि साधारण आदमी के भी इसका दस ग्राम का सिक्का खरीदने पर पसीने छूट गये। जहां तक सोने का प्रश्न है तो वह आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो चुका है। चांदी के दामों में तेजी की एक वजह यह भी है कि दुनिया भर के म्यूचल फंड इसके दामों में बन रही भविष्य गत तेजी को देखते हुए इसमें अपना निवेश बढ़ाने लगे हैं और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे-जैसे प्रगति हो रही है वैसे-वैसे ही इसकी मांग बढ़ रही है। चांदी के बढ़ते टैक्नोलॉजी क्षेत्र के उत्पादों में उपयोग से इसकी मांग लगातार बढ़ते रहने की ही उम्मीद है जिसकी वजह से सप्लाई सीमित होने पर इसके दाम दिन दूने और रात चौगुने के हिसाब से बढ़ रहे हैं। जनवरी 2025 में चांदी के दाम 85 हजार 913 प्रति किलो थे जो दिसम्बर 2025 तक बढ़कर दो लाख 47 हजार रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गये। इस दौरान चांदी की मांग में विश्व भर में दोगुनी के लगभग वृद्धि दर्ज हुई। चांदी की खपत में लगातार तेजी होने के कारण इस धातु की मांग अमेरिका जैसे देश में भी बढ़ी है और निवेशकों का इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। अमेरिका का केन्द्रीय फैडरल बैंक जहां अपनी ब्याज दरों में लगातार कमी कर रहा है उससे इस देश के बड़े निवेशक चांदी में अपना निवेश लाभप्रद समझ रहे हैं और इस धातु की जमकर खरीदारी कर रहे हैं परन्तु यह रवायत केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है क्योंकि विश्व के प्रतिष्ठित बैंक तक चांदी का स्टॉक रखना सुरक्षित समझ रहे हैं जिससे मुद्रा बाजार की ऊंच-नीच का वह मुकाबला कर सकें। चांदी का सर्वाधिक उपयोग बैटरी व सोलर पैनल बनाने में होता है और भविष्य में इनसे सम्बन्धित उद्योगों का भविष्य बहुत उज्वल माना जा रहा है जिसकी वजह से निवेशक चांदी में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही कृत्रिम ज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) उद्योग के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली टैक्नोलॉजी में भी चांदी का प्रयोग होता है और यह उद्योग चमकता क्षेत्र (सनराइज इंडस्ट्री) माना जा रहा है अतः चांदी की मांग लगातार बढ़ते रहना लाजिमी है। इस उद्योग में ट्रांसमिशन व स्मार्ट ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चांदी का उपयोग होता है अतः इस धातु की मांग लगातार बढ़ती ही रहेगी और सप्लाई सीमित होने की वजह से इसके दाम भी आने वाले सालों में आकर्षक ही बने रहेंगे। साथ ही पूरी दुनिया में चांदी का उपयोग आभूषण व सिक्के बनाने में भी होता है अतः इसकी पारंपरिक मांग भी बदस्तूर बनी रह सकती है। चांदी का उत्पादन अन्य खनिजों के उत्पादन के उप उत्पाद की तरह ही होता है। पिछले कई वर्षों से इसके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसे देखते हुए ही पिछले साल नवम्बर महीने में अमेरिका ने इस धातु को अत्यधिक संवेदनशील अलभ्य (क्रिटिकल) धातुओं की सूची में शामिल किया। मगर इससे पहले सितम्बर महीने तक ही अमेरिका में चांदी का स्टॉक 53 करोड़ 10 लाख औंस हो गया था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 74 प्रतिशत अधिक था। वर्तमान में अमेरिका में चांदी का कुल स्टॉक 44 करोड़ 90 लाख औंस बताया जाता है जो कि पारंपरिक स्टाक से तीन गुना है। इसके विपरीत चीन ने चांदी के निर्यात पर विगत 1 जनवरी से नये प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। अमेरिका में चांदी के भारी स्टाक की वजह से लन्दन के धातु स्टाक एक्सचेंज में चांदी की सप्लाई में कमी हो चुकी है। इसकी हाजिर डिलिवरी बहुत घट गई है और इसी बाजार से चांदी के अन्तर्राष्ट्रीय दाम तय होते हैं। अतः जैसे-जैसे चांदी की मांग बढ़ रही है और इसकी सप्लाई घट रही है वैसे-वैसे ही इसके दामों में उछाल आता जा रहा है। निकट भविष्य में यह क्रम कब तक चलेगा इसके बारे में फिलहाल बाजार विशेषज्ञ मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं।

सम्पादकीय...

स्वीकार करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए

नव वर्ष की शुभकामनायें, मतलब बिलेटेड वाली। यह नया साल सबके लिए खुशियाँ लाये। सभी स्वस्थ रहें। बेरोजगारों को रोजगार मिले और सभी को महंगाई से मुक्ति। पेट्रोल पैंतालिस पर आ जाये और डॉलर साठ के आसपास बना रहे। आगे से नववर्ष सदियों में तो आए पर सर्दी और वायु प्रदूषण का गठजोड़ टूट जायेग कहीं मैं कुछ ज्यादा कामना तो नहीं कर रहा। वैसे नया साल कुछ अच्छी खबरें ले कर नहीं आया है। अमेरिका वेनेजुएला में पहुंच गया है। वहां के नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनायें देने। वहां के राष्ट्रपति महोदय ने शुभकामनायें लेने में थोड़ी आनाकानी की तो ट्रंप जी ने उन्हें पकड़ कर अमेरिका ही बुला लिया और नववर्ष की शुभकामनायें पर्सनली दीं। इससे शिक्षा मिलती है कि आगे से अमेरिकी राष्ट्रपति अगर नववर्ष की शुभकामनायें दें तो उसे स्वीकार करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए नहीं तो वे पकड़ कर अमेरिका बुला लेंगे और जेल में डाल देंगे। इस नववर्ष की यह पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा भी अमेरिका से ही सम्बंधित है। अमेरिका को दूसरे देशों की जनता की भलाई और उनके लोकतंत्र से बहुत प्यार है। नहीं, नहीं अपने देश की जनता से नहीं, कुछ दूसरे देशों की जनता से। विशेष रूप से ऐसे देशों की जनता से जहाँ की जमीन से तेल खूब निकलता हो। और साथ ही यह भी कि वहां की सरकार अमेरिका की पिट्ठू ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति, चाहे कोई से वाले रहे हों, तेल निकालने वाले देशों से और वहां की जनता से बहुत प्यार करते हैं। अगर किसी देश में तेल नहीं निकलता हो तो वहां की जनता के दुख दर्द और लोकतंत्र से अमेरिका को कोई सरोकार नहीं है। हमारा देश भी उसी केटेगरी में आता है। इस साल के शुरू में ही ट्रंप जी ने हमारे देश पर पांच सौ पर्सेंट टैरिफ लगा दिया है। सच कहें तो लगाने का प्रस्ताव रख दिया है। जब से ट्रंप जी ने यह टैरिफ का खेल शुरू किया है तब से हमारे देश के सरकारी नेता हमें यह समझाने में लगे हैं कि अमेरिका द्वारा लगाया जा रहा बढ़ा हुआ टैरिफ देश के भले और उद्योगों की उन्नति के लिए कितना आवश्यक है। यही अमेरिका पहले जब सौ प्रतिशत टैरिफ लगा रहा था तब भी मंत्री लोग हमें यही समझा रहे थे। तो इस नववर्ष की तीसरी शिक्षा यह है कि अमेरिका अगर अधिक टैरिफ लगाता है तो वह देश की उन्नति के लिए अच्छा है। अगर अधिक टैरिफ इतना ही लाभप्रद है तो अच्छा होगा कि हमारे सरकार जी अमेरिका जा कर ट्रंप जी से निवेदन करें कि इस टैरिफ को हजार फीसदी कर दिया जाये। हमें बहुत खुशी होगी और देश उन्नत होगा। नया साल यहाँ भी अच्छी तरह आया। यहाँ नववर्ष अच्छा बनाने की जिम्मेदारी न्यायालय ने ली है। पिछले वर्ष के अंत में बलात्कार के, कत्लों के एक प्रभावशाली अपराधी को बेल दे दी (वैसे इस केस में उच्चतम न्यायालय ने बेल कैंसिल कर दी है) और इस साल के शुरू में दो आरोपियों की बेल अर्जी ठुकरा दी। चलो यह तो कोर्ट का अधिकार है, वह जैसे चाहे वैसे प्रयोग करे पर उस पर तुर्रा यह कि आप एक साल तक बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक ही तो है, कौन बार बार बेल रिजेक्ट करने का सिरदर्द ले। पिछले वर्ष हम हिन्दुओं ने बहुत गर्व किया।

अमेरिकी मनमर्जी को रोकने के लिए विश्व को एक होना पड़ेगा

1995 में एक फिल्म आई थी, गैम्बलर। गोविंदा-शिल्पा शेट्टी अभिनीत इस फिल्म का एक गाना उन दिनों बेहद मशहूर हुआ था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने ये गाना नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने हाल ही में न्यूयार्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जो कहा है, उसका भावार्थ कुछ यही निकलता है। उन्होंने कहा है, सिर्फ मेरा दिमाग ही मुझे रोक सकता है। मेरी अपनी नैतिकता और अपना दिमाग। यही वे चीजें हैं, जो मुझे रोक सकती हैं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है और न ही इसकी जरूरत। तीन जनवरी को वेनेजुएला में की गई अमेरिकी कार्रवाई के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप का इन शब्दों का प्रयोग करना दुनिया के लिए निश्चित तौर पर डरावना है। ट्रंप और उनकी सोच पारंपरिक लोकतांत्रिक मुखौटाबाज राजनीति से अलग है, लिहाजा वे खुलकर ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सुपर पावर के रूप में स्थापित होने के बाद से ही अमेरिका की सोच और कार्यशैली ऐसी ही रही है। अमेरिका की सत्ता में दो ही पार्टियों का वर्चस्व है। चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के राष्ट्रपतियों की कार्यशैली कम से कम विदेश मामलों में एक जैसी ही रही है। ट्रंप खुलकर 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति और नीयत का हवाला देते हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्रपति ऐसा कहने से बचते रहे हैं। हां, उनके भी कदम हमेशा ऐसा ही रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई हो, खाड़ी युद्ध हो, सूडान स्थित अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले के बाद अमेरिकी कार्रवाई हो, वियतनाम का युद्ध हो, ईरान पर कार्रवाई हो, हर जगह अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करता रहा है। बेशक उसे कई बार मुंह की खानी पड़ी है। हाल ही में ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन की सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर भाग खड़ी हुईं। वियतनाम का युद्ध लंबा चला था। इसे शुरू किया था डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने और जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंसता नजर आया तो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन ने सेनाओं की वापसी कराई। कुवैत पर जब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने हमला किया, तब जार्ज बुश सीनियर राष्ट्रपति थे। अमेरिका में एक धारणा रही है कि कुवैत पर कब्जे की कार्रवाई इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी इशारे पर ही की थी। लेकिन जब मामला उल्टा पड़ गया तो जॉर्ज बुश सीनियर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की आड़ में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ गठबंधन करके सैनिक कार्रवाई शुरू की। 1990 में अमेरिकी कार्रवाई के चलते इराकी गार्ड को कुवैत को खाली करना पड़ा। इसके बाद इराक अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया। वैसे लंबे समय तक चले ईरान-इराक युद्ध के पीछे भी अमेरिकी हित काम कर रहे थे। तब दुनिया दो ध्रुवीय थी। एक तरफ सोवियत संघ की अगुआई में विश्व का एक बड़ा हिस्सा काम कर रहा था तो दूसरी ओर अमेरिकी अगुआई में ज्यादातर नाटो देश सक्रिय थे। अफगानिस्तान में जब पिछली सदी के अस्सी के दशक में सोवियत सेनाएं घुसीं, तब सोवियत संघ को काबू करने के लिए अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान का उपयोग किया और एक तरह से पाकिस्तान को अपना अघोषित उपनिवेश बना लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 और 1971 के युद्धों में अमेरिका में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, अमेरिकी सेनाओं और सरकार ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया और भारत का विरोध किया। साल 2024 में हुए बांग्लादेश में विद्रोह और शेख हसीना के तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी एजेंसियों के हाथ को लेकर संदेह जताया जाता है। साल 2010 के दिसंबर में ट्यूनिशिया में शुरू हुई पिंक क्रांति, जिसे अरब क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, की बुनियाद पर अरब देशों में कार्रवाई करने और तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी एजेंसियों के सहयोग को देखा जाता है। अमेरिकी एजेंसियों की ही शह पर लीबिया से गद्दाफी की विदाई हुई, सीरिया अब भी जल रहा है। निश्चित तौर पर अमेरिकी प्रतिकार में शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष काम करता था, अब दुनिया की दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बन चुका चीन कर रहा है। हाल ही में वेनेजुएला के जिन मादुरो की सत्ता को अमेरिकी सेनाओं ने पलट दिया, उन्हें चीन का खुला समर्थन मिल रहा था। शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ और उसकी सेना ऐसे हालात में अमेरिकी सेनाओं का परोक्ष विरोध करती थी, वैसा चीन नहीं कर पाया। कह सकते हैं कि अमेरिका में हर सत्ता ने वैश्विक ताकत क्रम में खुद को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से दादागिरी दिखाई है। कभी यह दादागिरी अमेरिकी हितों के नाम पर हुई तो कभी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर। कहने के लिए अमेरिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरुआ बनता है, लेकिन अमेरिकी हितों, कारोबारियों और हथियार लॉबी के हित में अक्सर वह गैर लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई करता है। दुनिया का आधुनिक इतिहास इससे भरा पड़ा है। वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है। ट्रंप जिन अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अपने हिसाब से मानने या न मानने की बात कर रहे हैं, दरअसल उन्हें बनाने और संशोधित करने में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का ही रहा है।

विश्व में जब भी कहीं वेनेजुएला जैसी घटना होती है, तब जिनेवा समझौते और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का बहुत जिक्र होता है। दरअसल उन्नीसवीं सदी के मध्य तक दुनिया में होने वाले युद्धों के लिए युद्धबंदियों और सैनिकों और युद्धग्रस्त देशों के लोगों को लेकर शत्रु देशों की ओर से की जाने वाली अमानवीय कार्रवाई को रोकने के लिए ना तो कोई कानून था और इसे लेकर कोई प्रयास हुआ था। साल 1864 में पहली बार युद्ध के वक्त घायलों की मदद युद्धरत देशों के बीच बातचीत के लिए रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट ने कोशिश की। वही कोशिश पहले जेनेवा समझौते के रूप में सामने आई। इस दौरान युद्धरत देशों, उनके नागरिकों, सैनिकों आदि के मानवीय अधिकारों की रक्षा करने को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं। इसके तहत कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परिकल्पना की गई और युद्ध के प्रभाव को सीमित करने और युद्धबंदियों के अधिकारों के संरक्षण की कोशिश शुरू हुई। जेनेवा में आखिरी समझौता 1949 में हुआ। जिनेवा कन्वेंशन का मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिये कानून तैयार करना है। 1949 के समझौते में शामिल दो प्रोटोकॉल 1977 में जोड़े गए। आज तकरीबन पूरी दुनिया ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इस लिहाज से जेनेवा समझौते को सभी देश मानते हैं। जेनेवा समझौते के अनुसार हर देश की अपनी संप्रभुता है और उसकी रक्षा ना सिर्फ युद्ध बल्कि शांति काल में भी होती है। यानी उसके नियम और कानून युद्ध, शांति और संकट काल, हर वक्त लागू होते हैं। इस संदर्भ में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना कि उनकी अपनी नैतिकता ही उन्हें किसी भी कार्रवाई से रोक सकती है। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि जहां उन्हें लगेगा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून मानना चाहिए, वहां तो उसे वे मान लेंगे और जहां नहीं लगेगा, वहां नहीं मानेंगे। अमेरिकी दादागिरी के इतिहास में ट्रंप का यह बयान दुनिया की सोच से आगे है। चीन, ब्राजील और भारत के खिलाफ वे टैरिफ युद्ध चला ही रहे हैं, रूस से तेल खरीदने के आरोप की आड़ में वे तीनों देशों पर अब 25 प्रतिशत की बजाय पांच सौ प्रतिशत टैरिफ थोपने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की जैसी फितरत है, उसकी वजह से उनसे कोई सकारात्मक उम्मीद रखना बेमानी ही है। भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकवाने को लेकर उनका कल्पित दावा हो या फिर ग्रीनलैंड, कोलंबिया, ईरान, मैक्सिको और क्यूबा को लेकर दी गई धमकी, सभी अमेरिकी दादागिरी का ही उदाहरण है। माना जा रहा है कि वे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप पहले ही कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर चुके हैं और इस तरह अपने पड़ोसियों और यूरोप के अपने पारंपरिक सहयोगियों को ना सिर्फ आशंकित, बल्कि नाराज भी कर चुके हैं। अमेरिकी दादागिरी पूरी दुनिया देखती और समझती रही है।

लेकिन एक साथ इतने मोर्चे खोल देने की ट्रंप की नीति के खिलाफ अमेरिका में ही आवाजें उठने लगी हैं। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कहना कि वेनेजुएला में की गई कार्रवाई की जरूरत नहीं थी और इससे अमेरिका को लेकर संघर्ष बढ़ेगा, एक तरह से अमेरिका की बढ़ती चुनौतियों का ही संकेत देता है। ट्रंप की मनमानी नहीं रुकी, अमेरिकी दादागिरी का ऐसा ही दौर उन्होंने जारी रखा तो आने वाले दिन दुनिया के लिए भले ही चुनौतीपूर्ण होंगे,अमेरिका भी कई तरह की चुनौतियों और वैश्विक प्रतिरोध को झेलने के लिए अभिशप्त हो जाएगा। शांति की चाहत रखने वाली दुनिया को अमेरिकी मनमर्जी पर कहीं न कहीं रोक तो लगानी ही होगी।

चीन से क्या हम भाषायी बोध सीख सकते हैं

हिंदी के संदर्भ में देखें तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच शाब्दिक ही नहीं, भावात्मक फर्क भी है। फिर भी एक बड़ा वर्ग हिंदी को राष्ट्रभाषा भी मानता है। यही वजह है कि हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के नौवें महीने की दस्तक के साथ ही, हर सरकारी दफ्तर राजभाषा पखवाड़े या महीने को लेकर उत्साह से भर उठता है। कुछ ऐसा ही पड़ोसी चीन में भी अब होता नजर आ रहा है। अब वहां सितंबर का तीसरा सप्ताह 'राष्ट्रीय सामान्य भाषा और लिपि' को समर्पित होगा। भारत और चीन के सितंबर महीने के भाषायी उत्साह में एक अंतर रहेगा, राष्ट्रभाषा बनाने की आस में हिंदी के राजभाषा ओहदे को याद किया जाएगा, जबकि चीन अपनी मंदारिन भाषा को बाकायदा राष्ट्रभाषा के तौर पर और आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होगा। भाषायी चिंतन और व्यवहार को लेकर भारत और चीन को लेकर तकरीबन एक ही सोच है। भारत में एक मानस ऐसा है, जिसे हिंदी की कीमत पर भी पर अंग्रेजी स्वीकार्य है। यह धारा मानती है कि वेगवान आर्थिक विकास की वजह से चीन का भाषायी व्यवहार भी इसी भारतीय मानस की तरह बदल चुका है। बेशक चीन ने अंग्रेजी सीखने-सिखाने की दिशा में भरपूर निवेश किया है। अपनी आर्थिक ताकत के चलते पश्चिम के नामी विश्वविद्यालयों में चीनी सत्ता प्रतिष्ठान अपने लिए अध्ययन पीठ स्थापित कर चुका है। गौर करने की बात है कि उसने यह सब अलग और अतिरिक्त अनुशासन और ज्ञान के साधन के तौर पर किया है, भारत की तरह अपनी भाषा, विशेषकर हिंदी की कीमत पर ऐसा नहीं किया है। अंग्रेजी का पहला वैश्विक विस्तार ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौर में हुआ और दूसरी बार उसका प्रसार रीगन-थैचर की जोड़ी के आर्थिक उदारीकरण के बढ़ते कदमों के साथ हुआ। इस संदर्भ में चीन और भारत के भाषायी चिंतन और व्यवहार फर्क साफ नजर आता है। पिछली सदी के अस्सी के दशक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख देंग शिआओपिंग ने आर्थिक खुलेपन की नींव रखी। यह 1978 का साल था। इसके ठीक दो साल बाद भारत में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और उन्होंने भी धीरे-धीरे इंस्पेक्टर राज कम करने की शुरुआत की। उनकी उदारीकरण की सोच को राजीव गांधी ने परवान चढ़ाया। 1991 के आम चुनावों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पहली बार समाजवादी आर्थिक नीतियों के बरक्स उदारीकरण का वादा किया। तब से अब तक की दोनों देशों की आर्थिक विकास यात्रा को देखें तो अंतर साफ नजर आता है। चीन आज अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। उसकी तेज आर्थिक यात्रा के समानांतर अंग्रेजी का विस्तार नहीं दिखता। जबकि भारत में इसके ठीक उलट नजारा दिखता है। उदारीकरण के बरक्स दोनों देशों के भाषायी चिंतन में भी फर्क नजर आता है। यह फर्क ही है कि चीन अब अपनी मंदारिन भाषा और उसकी लिपि को लेकर सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते को समर्पित कर रहा है। चीन की सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था 'राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा' की स्थाई समिति द्वारा बीते 27 दिसंबर को इससे जुड़ा कानून पारित करना इसी सोच का प्रतीक है। इस कानून में हर वर्ष सितंबर के तीसरे सप्ताह को 'राष्ट्रीय सामान्य भाषा और लिपि संवर्धन एवं प्रचार सप्ताह' के रूप में मनाना तय किया गया है। यह कानून पुराने राष्ट्रीय भाषा कानून में संशोधन के बाद आया है। चीन में दो तरह की मंदारिन का प्रयोग होता है, एक लिखित और दूसरी मौखिक। इस कानून में दोनों तरह की भाषाओं का ध्यान रखा गया है। चीन अपनी भाषा और लिपि को अपने राष्ट्र का प्रतीक मानता है। चीन में इन दिनों प्रौद्योगिकी और डिजिटल जगत में लगातार प्रगति हो रही है। यहां ऑडियो-विजुअल प्रोग्रामिंग और गेमिंग भी बढ़ी है। चीन का भाषायी कानून इन सबमें इस्तेमाल होने वाली भाषा के साथ कदमताल करने का प्रयास है। कहा जा सकता है कि चीनी राष्ट्रभाषा और लिपि कानून में यह संशोधन तेजी से विकसित हो रही संचार प्रौद्योगिकियों और ऑनलाइन सामग्री के विस्तार के बीच भाषा के मानकीकरण को मजबूत करने की कोशिश है। इस कानून में साइबरस्पेस प्रशासन को लेकर भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत अब ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वेब सीरीज, ऑनलाइन फिल्मों, ऑनलाइन गेम और अन्य डिजिटल प्रकाशनों में मानक चीनी भाषा यानी मंदारिन और मानकीकृत चीनी अक्षरों को मूल भाषा के रूप में उपयोग करना जरूरी होगा। इसके साथ ही चीन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, कॉन्फ्रेंस, इवेंट्स आदि के साइनबोर्ड, लेबल या प्रमोशनल मैटीरियल में विदेशी भाषाओं के साथ ही मानक चीनी भाषा भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसकी तुलना में भारतीय राष्ट्रभाषा और आधुनिक प्रौद्योगिकी संग उसके तालमेल पर नजर डालें साफ फर्क नजर आता है। भारत अब भी राष्ट्रभाषा से दूर है। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाली ताकतों के सुर भी अब धीमे पड़ते जा रहे हैं। लेकिन चीन अपने आर्थिक उदारीकरण के बावजूद अपनी भाषा की ओर लौटता नजर आ रहा है। इसके साथ ही चीन के भाषायी आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है। यहां की करीब 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी मंदारिन बोल सकती है। चीन में करीब 97.33 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इनमें करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा लोग मानक चीनी अक्षरों का प्रयोग करते हैं। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंटर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते जून तक चीन में एक अरब 12 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर थे। इसी रिपोर्ट के अनुसार, चीन में इंटरनेट इस्तेमाल की दर 79.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। भाषायी कानून में इन आंकड़ों के मद्देनजर सरकारी और पब्लिक सर्विस वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए भी सरकारी नियमों और मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय मानक भाषा का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। इस कानून का लक्ष्य चीनी राष्ट्र के प्रति मजबूत सामुदायिक भावना का विकास और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की मजबूती है। कानून इस बात पर भी जोर देता है कि बोली और लिखी जाने वाली मानक चीनी भाषा के इस्तेमाल का मकसद राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और जातीय एकजुटता बनाना होना चाहिए। यह कानून शिक्षा में भी मानक चीनी भाषा की भूमिका पर जोर देता है। कानून के अनुसार, शिक्षण और पाठ्य सामग्री में मानक मंदारिन ही बुनियादी भाषा होगी। यह भारत की नई शिक्षा नीति जैसा ही है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं के जरिए शिक्षण पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत संस्कृति, पर्यटन और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में सर्विस देने वाले कर्मचारियों के लिए मानक मंदारिन जानना जरूरी होगा। इस कानून में मानक चीनी सीखने या प्रयोग में बाधा डालने पर सजा का प्रावधान भी है। हालांकि पहले उन्हें इसके लिए आगाह किया जाएगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि भारत में भाषा को नकारने को लेकर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। वैसे इस कानून के दुरुपयोग की चिंता भी जताई जा रही है। चीनी संविधान और जातीय स्वायत्तता व्यवस्था के तहत, स्वायत्त क्षेत्रों मसलन, तिब्बत, शिनजियांग, इनर मंगोलिया, गुआंग्शी, निंग्शिया आदि को क्षेत्रीय स्वायत्तता कानूनों के अनुसार, सरकारी कार्यों, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी में राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ एक या अधिक स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल का प्रावधान है। लेकिन शी जिनपिंग के शासन में ये प्रावधान कमजोर होते गए हैं। इसका असर तिब्बत में दिखता है, जहां कई सालों से चल रहे मातृभाषा आंदोलन और सांस्कृतिक शिक्षा का दमन किया गया। इसकी वजह से वहां निजी स्कूल बंद कर दिए गए और उनके संस्थापक गिरफ्तार कर लिए गए। तिब्बतियों को आशंका है कि इस कानून के तहत उनके खिलाफ दमन का एक और चक्र शुरू हो सकता है। साल 1994 में फ्रांस ने अपने यहां अंग्रेजी के बिलावजह प्रयोग को कानून के जरिए रोक लगाई थी। अब चीन का अपनी मानक भाषा को स्थापित करने का कानून आया है। यह सब देखते हुए भी भारत की मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर ऐसे कानून का सुझाव देना भी संभव नहीं लगता। लेकिन चीन के इस भाषायी बोध के बहाने अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि एक दिन भारत में भी ऐसी सोच जरूर विकसित होगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने चन्दन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीतमपुरा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

मकर संक्रांति पर आज कुन्दरकी विधानसभा में होगा अनूठा कार्यक्रम

मुरादाबाद।

कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह कल मकर संक्रांति के अवसर पर कुंदरकी विधानसभा के ग्रामों और नगर पंचायत में अलग - अलग 305 स्थानों पर सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन करा रहे हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधायक मीडिया प्रभारी रचित गुप्ता ने बताया कि कल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा अनूठा आयोजन कराया जा रहा है। कुंदरकी विधानसभा में 305 स्थानों पर सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन होगा। प्रत्येक स्थान पर लगभग 400 से अधिक लोग खिचड़ी भोज में सम्मिलित होंगे, इस प्रकार से लगभग सवा लाख लोग इस आयोजन में सहभागी बनेंगे। खिचड़ी भोज के लिए एसडीएम, तहसीलदार, ग्राम

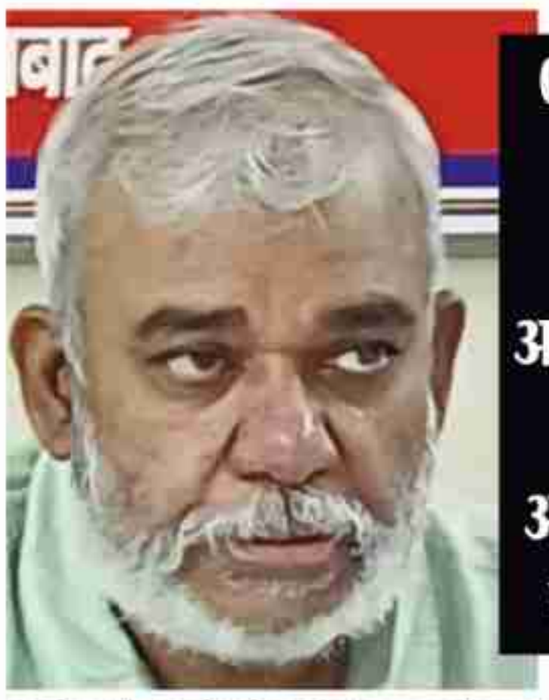

05 स्थानों पर सवा लाख से अधिक लोग बनेंगे आयोजन में सहभागी

प्रधानों, पूर्व प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों, लेखपाल, कानूनगो, सचिव, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, स्वच्छता कर्मी, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, रसोईया माता, शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी, बीट इंचार्ज, बीट कांस्टेबल सहित सभी थानाध्यक्ष, समाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, ग्राम और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह स्वयं भदासना, मुंडापांडे, अहरौला, रोंडा, लालाटीकर, रसूलपुर नंगली, नानपुर, नया गांव, डोमघर, कुंदरकी सहित 22 स्थानों पर आयोजित भोज में उपस्थित रहेंगे। साथ ही विधायक प्रतिनिधि विक्की ठाकुर ब्लॉक प्रमुख मुंडापांडे डॉ नवदीप यादव आदि प्रमुख नेतागढ़ अलग अलग जगह कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। कुंदरकी विधानसभा में चार मंडलों मुंडापांडे, दलपतपुर, कुंदरकी और रतनपुर कलां में सेक्टर और ग्राम के अनुसार कार्यकर्ताओं को खिचड़ी भोज कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिम्मेदारी दी गई है। खिचड़ी भोज में सभी वर्गों के लोगों एक साथ बैठकर समरसता, सौहार्द और आपसी सहयोग को मजबूत करेंगे।

वृद्ध जन आवास एवं वृद्ध आश्रम में बांटे 12 वॉकर

मकर संक्रांति पर कर्म योग संस्थान का सराहनीय कार्य

मुरादाबाद।

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कर्म योग संस्थान द्वारा मिलन विहार स्थित वृद्ध आश्रम में 12 वॉकर प्रदान करने का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव एल. वेंकटेश्वर लू की धर्मपत्नी श्रीमती फणि लू उपस्थित रहीं। संस्थान की अध्यक्ष पिंकी दुमीर, प्रबंधक मनोज दुमीर और कोषाध्यक्ष करन दुमीर के नेतृत्व में अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग, मुरादाबाद मंडल के उपनिदेशक मोहम्मद मुश्ताक अहमद, तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि श्रीमती फणि लू ने वृद्धजनों को संबोधित किया और उनके साथ बहुत अ'छा समय व्यतित किया तथा वृद्धजनों की सेवा में सदैव ततपर रहने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दीपिका दुमीर, मोहित आनंद तथा संस्थान के अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

वाराणसी की घटना से भड़के कांग्रेसी

जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, बोले-नहीं होने देंगे लोकतंत्र की हत्या

मुरादाबाद।

वाराणसी की घटना को लेकर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से बुद्धवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर घटना की उ'ा स्तरीय जांच कराये जाने की माग की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 11 जनवरी को वाराणसी में एसआईआर और वोट चोरी के विरोध में एन.एस.यू.आई. के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे।

विरोध प्रदर्शन के दौरान एन.एस.यू.आई. के कार्यकर्ताओं के साथ एन.एस.यू.आई. के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूण चौधरी के साथ पुलिस द्वारा जिस प्रकार का बर्ताव किया गया उसे स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही साथ पुलिस द्वारा इन कार्यकर्ताओं को लॉकअप में बन्द कर दिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी एन.एस.यू.आई. के कार्यकर्ताओं के घरों पर पहुँच कर ब'चों एवं महिलाओं को परेशान किया गया। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस द्वारा किये गये इस प्रकार के दुव्यवहार एवं दमनकारी रणनीति की घोर भत्सना करती है और मांग करती है कि लोकतंत्र को कुचलने की सोच रखने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ उच स्तरीय जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर, महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम, महफूज अली राजा, विवेक अग्रवाल, श्याम बाबू, बन्ने पहलवान, मौ. अनस, वसीम, अमीरूल हसन जाफरी, दानिश सैफी, बब्बन खाँ, मौ. हनीफ आदि मौजूद रहे।

विश्वकर्मा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

मुरादाबाद।

प्रधानाचार्य राजकीय आई.टी.आई. मुरादाबाद ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत तृतीय स्तर पर रजिस्टर्ड/ प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों हेतु पीएम विश्वकर्मा-जागरूकता कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को उत्पाद का मूल्य निर्धारण बाजारीय विश्लेषण वित्तीय एंव डिजीटल साक्षरता, विक्रय योजना, पैकेजिंग डिजाइनिंग का महत्व, ऑनलाइन उत्पाद का विक्रय, ई-कॉमर्स की महत्ता एंव क्यू आर कोड का उपयोग से अवगत कराया गया। साथ ही साथ कार्यशाला में अवधेश कुमार एम.एस.एम.ई. विकास कार्यालय आगरा द्वारा उनके मंत्रालय से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी गयी। योगेश कुमार संयुक्त आयुक्त, जिला उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मुरादाबाद, पंकज सरन मुख्य प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक मुरादाबाद, अमरपाल सिंह कार्यदेशक, एस.वी. रस्तौगी असिस्टेन्ट प्रोफेसर तीर्थंकर विश्वविधालय, अनमोल पाण्डेय प्रशिक्षक, ऋचा वार्ष्णेय प्रवक्ता राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर की उपस्थिति के साथ-साथ उनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं, वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण, उद्यमिता एंव उत्पादों के बाजार में विक्रय तकनीक के विभिन्न आयामों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को उत्पाद का मूल्य निर्धारण बाजारीय विश्लेषण वित्तीय एंव डिजीटल साक्षरता, विक्रय योजना, पैकेजिंग डिजाइनिंग का महत्व, ऑनलाइन उत्पाद का विक्रय, ई-कॉमर्स की महत्ता एंव क्यू आर कोड का उपयोग से अवगत कराया गया।

17 तक बंद रहेंगे 8 वीं तक के स्कूल

मुरादाबाद। जनपद में अत्यधिक शीतलहर और घने कोहरे के मद्देनजर प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद, जिले के सभी प्रकार के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।जारी आदेश के अनुसार, परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और अन्य सभी बोर्ड से संचालित कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 17 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। यह निर्णय लगातार गिरते तापमान और सुबह के समय घने कोहरे से ब'चों को होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों को समय पर अवकाश की जानकारी देने को कहा गया है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में भी शीतलहर का असर बने रहने की संभावना है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

एसएसपी के निर्देश पर चला बैंक चैकिंग अभियान

मुरादाबाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देश पर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बैंक चेकिंग अभियान चलाया।यह अभियान बुधवार को चलाया गया। जनपदीय पुलिस ने बैंकों, एटीएम और उनके आसपास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की गहनता से जांच की। पुलिस ने ग्राहकों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की अपील भी की।

हत्यारा मांझा ने समीर हाशमी को उतार दिया मौत के घाट

जौनपुर। जनपद के तमाम स्वयंसेवियों की बुलन्द आवाज एवं जिला प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक नहीं लग रही है। यही कारण है कि गत दिवस एक शिक्षक की मौत होने के बाद अब एक चिकित्सक की भी जान चली गयी। इतनी जागरूकता एवं हो-हल्ला होने के बावजूद भी चाइनीज मांझा चोरी छिपे बिक रहा है जिसका जीता-जगता उदाहरण बुधवार को उस समय देखने को मिला जब इसी हत्यारे मांझे की चपेट में आने से एक डाक्टर की मौत हो गयी। बता दें कि बुधवार को दोपहर नगर के लाइन बाजार के पचहटियां के पास केराकत के शेखजादा मोहल्ला निवासी डा. समीर हाशमी 25 वर्ष किसी मरीज को देखने के लिये जिला अस्पताल से वापस घर जा रहे थे कि रास्ते में पंचहटिया पुराने पोस्टमार्टम के सामने कटी पतंग के मांझे की चपेट में आने से उनकी गर्दन बुरी तरह से कट गयी। देखते ही देखते दुर्घटना स्थल खून से लथपथ हो गया जिसको देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया जिस पर घायल चिकित्सक को एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल ले जाया गया जहां गर्दन कटने एवं अधिक रक्तस्राव से डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के पिता मुकीम और भाई जावेद जिला अस्पताल पहुंच गये। बता दें कि 4 बेटों में डा. समीर सबसे छोटे जो परिवार के सहारा थे।

वहीं जानकारी होने पर क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता आईपीएस सहित तमाम प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गये। समाचार लिखे जाने तक शव को कब्जे में लेकर अन्त्य परीक्षण हेतु भेज दिया गया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिसिया कार्यवाही भी शुरू हो गयी।

डी फार्मा करके क्लीनिक चलाता था मृतक

मृतक 4 भाई व 4 बहनों में सबसे छोटा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डी फार्मा का ट्रेनिंग पूरी करके सिहौली चौराहे के समीप खुद की क्लिनिक खोल परिवार का भरण पोषण करता था। पिता कपिल हाशमी बैंड पार्टी चलाने का काम करते हैं। समीर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

चाइनीज मांझे से जनपद में हुई दूसरी मौत

इसके पहले चाइनीज मांझे की चपेट में आने से शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसा तब हुआ जब शिक्षक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ घर वापस लौट रहा था जिसके बाद शिक्षकों में चाइनीज मांझे को लेकर आक्रोश फूटा और तमाम लोगों ने जिला एवं पुलिस प्रशासन को पत्रक सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग को उठाई थी। जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी चाइनीज मांझे पर रोक नहीं लग पा रही है। आखिर कब तक बेवजह मासूम लोग अपनी जानें गवांते रहेंगे?

गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा हुआ दर्ज

घटना की सूचना पर पहुंचे सहायक पुलिस अधीक्षक/नगर क्षेत्राधिकारी गोल्डी गुप्ता आईपीएस ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही मांझा बेचने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है। मकर संक्रांति को लेकर उन्होंने कहा कि त्योहार पर पतंग उड़ने का रिवाज है। वह आप पूरा करें, मगर कृपया कर के काटन के धागे का उपयोग करें।

पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही

लोगों की मानें तो प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पर रोक लगाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। हाल ही में जिले में एक शिक्षक की भी इसी प्रकार की घटना में उस समय मौत हो चुकी है जब वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। यह घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि प्रतिबंधित मांझे के उपयोग को लेकर जागरूकता और सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है।

परिवार सहित क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर

समीर की मौत ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गयी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन को इस पर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिबंधित मांझे का उपयोग न केवल जानलेवा है, बल्कि यह समाज के लिये भी एक गम्भीर खतरा बन चुका है। समीर के परिवार में इस घटना से गहरा दुख छा गया है।

परिवार के जीविका का मुख्य माध्यम था मृतक

मृतक के पिता मुकीम ने कहा कि 4 पुत्रों में डा. समीर ही परिवार के जीविका का साधन था। ऊपर वाले ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। यह घटना न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे समाज के लिये दुखदायी है। चाइनीज मांझा बड़ी चेतावनी भी है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि इस प्रकार के मांझे की बिक्री पर सख्त कार्यवाही की जाय, ताकि भविष्य में किसी और की जान न जाय।

रील से रचना तक... साहित्य की ओर लौटते युवा किताबों के बीच खुद को तलाशते दिखे

नई दिल्ली। सोशल मीडिया वाले जमाने में मोबाइल स्क्रीन की तेज रफ्तार दुनिया से निकलकर जब युवा किताबों के पन्नों में ठहरने लगे है, तो यह बदलाव सिर्फ पढ़ने की आदत का नहीं, सोच का भी है। विश्व पुस्तक मेले में इस बार भीड़ सिर्फ नई किताबों की नहीं, बल्कि क्लासिक्स, प्रेम कथाओं और पराक्रम से भरी रचनाओं की ओर खिंचती दिखी। उपन्यासों, कविताओं और ऐतिहासिक गाथाओं के बीच युवा न केवल साहित्य को, बल्कि खुद को भी नए सिरे से खोजते नजर आए। हर स्टॉल युवा पाठकों से गुलजार रहा। एक युवा पाठक ने कहा, कि साहित्य से इश्क ने पुस्तक मेले में पहुंचा दिया है। कोई प्रेम उपन्यासों में खोया दिखा, तो कोई कविता संग्रह के पन्ने पलटता हुआ दिखा। एक युवा पाठक ने कहा, अगर किताबें न होतीं, तो शायद भावनाओं को समझना भी मुश्किल हो जाता। साहित्यकार इसे हिंदी और भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक जीत मान रहे हैं। उपन्यास, कविता, नाटक और निबंध हर विधा के दिग्गज लेखकों की किताबें स्टॉल्स पर प्रमुखता से सजी दिखीं। मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह 'दिनकर', महादेवी वर्मा, हरिवंशराय बच्चन, निराला, अज्ञेय, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, फणीश्वरनाथ रेणु और कमलेश्वर जैसे साहित्यकारों की कृतियां युवाओं के हाथों में बार-बार दिखीं। प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर किताबों की अलमारियों को निहारते एक युवती बार-बार पूछ रही थी, रेत की मछली नहीं मिल रही? युवक ने कोई दूसरी किताब लेने की सलाह दी, लेकिन युवती ने शांत स्वर में कहा रेत की मछली ही गुनाहों के देवता का जवाब है। लोकभारती प्रकाशन के स्टॉल संचालक बताते हैं कि युवा पाठक प्रेम को पुराने नजरिए से समझना चाहते हैं। इसीलिए निर्मल वर्मा, देवदास, मृणालिनी और गुनाहों का देवता जैसी क्लासिक प्रेम कथाएं खूब बिक रही हैं। प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर युवा आत्मकथाएं, जीवनियां और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी किताबें खरीदते दिखे। प्रभात प्रकाशन के निदेशक पीयूष कुमार बताते हैं, कि इन पुस्तकों के जरिए पाठकों को न केवल ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, बल्कि संघर्ष, आत्मबल और राष्ट्रप्रेम की भावना भी गहराती है। यही कारण है कि ऐसी किताबें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ आम युवा भी पढ़ना चाहते हैं। विश्व पुस्तक मेला में मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायु सेना के पायलट से लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक के अपने सफर के बारे में बताया। उन्होंने यह बातें एनबीटी-इंडिया के निदेशक युवराज मलिक की ओर से बच्चों और युवाओं के लिए संचालित खास सत्र में साझा कीं। कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि कड़ी मेहनत और लगन से उनमें से कोई भी भविष्य का अंतरिक्ष यात्री बन सकता है।

हरियाणा में फिर डोली धरती, घरों से बाहर निकले लोग

सोनीपत। सोनीपत में बुधवार दोपहर 12 बजकर 49 मिनट 39 सेकेंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। इसका केंद्र गोहाना क्षेत्र के गांव भैंसवाल कलां में जमीन से पांच किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप के झटके महसूस होते पर केंद्र के आसपास रहने वाले लोग घरों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकल गए। बता दें कि इससे पहले 21 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर में दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र झज्जर में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा के रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर और झज्जर में समय-समय पर भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ये सभी जिले जोन फैक्टर 0.16 यानी भूकंपीय जोन तीन में आते हैं।

पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर पोंगल समारोह में लिया हिस्सा, बोले- ये मेरे लिए सौभाग्य की बात

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संतुलन का संदेश देने वाला पोंगल अब वैश्विक पर्व बन गया है और दुनियाभर में तमिल समुदाय के लोगों ने इसे संजोकर रखा है। प्रधानमंत्री ने यहां केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में भाग लिया। मोदी ने कहा कि इस पर्व पर किसानों के परिश्रम का उत्सव मनाया जाता है और पृथ्वी तथा सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। समारोह में कई केंद्रीय मंत्री, नौकरशाह और अन्य वर्गों के लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा,''पोंगल का त्योहार हमें याद दिलाता है कि आभार शब्दों से आगे बढ़कर जताया जाना चाहिए और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाना चाहिए। जब धरती हमें इतना कुछ देती है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति को संजोने वाले लोग बड़े उत्साह से पोंगल मनाते है और उनके बीच आकर वह गौरव की अनुभूति कर रहे है। मोदी ने कहा कि तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसमें सदियों की बुद्धिमत्ता और परंपरा है जो इतिहास में सबक लेकर भविष्य का रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा, ''इस विरासत से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत आगे बढ़ने में इसकी सांस्कृतिक जड़ों से मजबूती लेता है। पोंगल के इस शुभ अवसर पर हम महसूस कर रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ाने वाली विश्वास और एकता की भावना इसकी संस्कृति से गहराई से जुड़ी है और इस धरा के लिए अपार सम्मान रखती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल का पर्व प्रकृति, परिवार और समाज के बीच सौहार्दपूर्ण संतुलन बनाकर रखने के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने कहा, ''मिट्टी की सेहत को बनाकर रखना, जल संरक्षित करना और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल आवश्यक है। मिशन 'लाइफ, 'एक पेड़ मां के नाम और अमृत सरोवर जैसी पहल इसी भावना पर आधारित है और ये हमें इन मूल्यों को कायम रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मोदी ने कहा कि पोंगल लोगों को सिखाता है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''आज पोंगल वैश्विक पर्व बन गया है। पिछले साल मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला, जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की साझा विरासत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना जाता है। उन्होंने कहा, ''तिरुकुरल (तमिल काव्य) में कृषि और किसानों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इससे पहले तमिलनाडु के लोगों और दुनिया भर में रह रहे तमिल समुदाय के लोगों को पोंगल पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने तमिल और अंग्रेजी भाषा में लिखे एक पत्र में कहा कि पोंगल उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है जो अपने परिश्रम से हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। उन्होंने कहा, '' प्रिय देशवासियों, वणक्कम (नमस्कार)! पोंगल के शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह विशेष त्योहार हमें मानव श्रम और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्योहार कृषि, मेहनतकश किसानों, ग्रामीण जीवन और काम की गरिमा से गहराई से जुड़ा हुआ है।

पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिरी, 29 की मौत

82 घायल, ज्यादातर स्कूली छात्र; 65 फीट ऊंचाई से मलबा गिरा, डिब्बे पटरी से उतरे

वर्ल्ड डेस्क। थाईलैंड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। दरअसल राजधानी बैंकॉक से थाईलैंड के उत्तर पश्चिमी प्रांत जा रही एक ट्रेन पर निर्माणाधीन सहट की क्रेन गिर गई। इसके बाद ट्रेन भी पटरी से उतर गई। इस हादसे में 29 लोगों की मौत हुई है और करीब 80 लोग घायल हैं। ये दुर्घटना बुधवार सुबह थाईलैंड के सिखियो जिले में हुई। यह क्षेत्र राजधानी बैंकॉक से करीब 230 किलोमीटर दूर है। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि हादसे में 22 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि बाद में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया। हादसे का शिकार हुई रेलगाड़ी उबोन रतचथानी प्रांत जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, जिस पर क्रेन काम में लगी थी, जब वहां से ट्रेन गुजर रही थी, तभी क्रेन वहां से गुजर रही ट्रेन पर गिर गई। क्रेन गिरने के चलते ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है और बचाव कार्य चल रहा है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बचाव कर्मी हादसाग्रस्त ट्रेन को काटकर घायल लोगों को निकाल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हादसे का शिकार हुई ट्रेन में 195 यात्री सवार थे। हालांकि ये आंकड़ा ट्रेन में सीटों के आधार पर बताया गया है और ट्रेन में असल में कितने यात्री सवार थे, इसका आंकड़ा अलग हो सकता है। थाईलैंड सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। हादसा बुधवार सुबह 9 बजे के करीब हुआ।

लाल किला बम धमाकाः डॉ. शाहीन सईद समेत पांच अन्य दोबारा एनआईए की हिरासत में

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार बम ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉ. शाहीन सईद सहित पांच आरोपियों को तीन दिन की हिरासत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है। कोर्ट ने एनआईए की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया, जिसमें एजेंसी ने धमाके की साजिश, फंडिंग, विदेशी हैंडलर और तकनीकी मदद से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए पूछताछ की जरूरत बताई थी।

आरोपियों में डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद, जसिर बिलाल वानी (उर्फ दानिश), डॉ. अदील अहमद और डॉ. मुजम्मिल शकील शामिल है। इन सभी को 16 जनवरी 2026 को दोबारा कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इससे पहले, डॉ. शाहीन सईद को पिछले महीने न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि जांच में कई कड़ियां अभी सुलझानी बाकी है। धमाके की पूरी साजिश, फंडिंग के स्रोत, विदेशी हैंडलरों के संपर्क और तकनीकी सहायता से जुड़े राज खुलने बाकी हैं। एजेंसी ने इन आरोपियों से गहन पूछताछ की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। यह मामला 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए भीषण धमाके से जुड़ा है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि यह धमाका एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे डॉ. उमर उन नबी मुख्य भूमिका में थे। डॉ. उमर कार में मौजूद थे और धमाके में उनकी मौत हो गई थी।

भाजपा का 'बहिष्कारड्रामा, अब परदेसी ताकतों का कर रही है स्वागतः अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और उसके संगी-साथी स्वदेशी का नारा लगाते-लगाते अब परदेसी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक चीन से आयात और चीनी सामान के बहिष्कार की बातें कर रहे थे, वही आज खुलेआम उसका स्वागत कर रहे हैं। बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के वैचारिक उस्ताद पड़ोसी देश से एकदलीय व्यवस्था का मास्टर क्लास ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्तर तक अब मुलाकात पहुंच गई है, उससे साफ है कि इसकी तैयारी कई वर्षों से चल रही थी। ऐसे में बहिष्कार का यह सारा ड्रामा केवल समर्थकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा समर्थक, जो चीनी सामान के बहिष्कार के लिए घर-घर जाकर प्रचार कर रहे थे, आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के ये समर्थक 'रंगे सियारों' की कहानी भूल गए थे, जिसका सच बारिश में सामने आ जाता है। अखिलेश यादव ने भाजपा की नीतियों और कथनी-करनी के अंतर पर सवाल उठाते हुए, जनता से सच समझने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की टूटी कमर, 29 माओवादियों ने डाले हथियार

सुकमा। बुधवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के सहयोगी संगठनों के 29 नक्सलियों ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे दरभा मंडल में माओवादी प्रभाव को एक बड़ा झटका लगा है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने पुणे मार्गेम पुनर्वास पहल के तहत हुए इन आत्मसमर्पणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की नीति और हाल ही में गोगुंडा में स्थापित सुरक्षा शिविर को एक महत्वपूर्ण माओवादी गढ़ को नष्ट करने का श्रेय दिया।

इस समूह में गोगुंडा में दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन (डीएकेएमएस) के प्रमुख पोडियम बुधा भी शामिल थे, जिन पर 2 लाख रुपये का इनाम था। इनके अलावा, डीएकेएमएस, मिलिशिया और जनताना सरकार के सदस्य भी इसमें शामिल थे।

सुरक्षा और समाज में पुनर्एकीकरण के वादों से प्रभावित होकर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गोगुंडा का दुर्गम इलाका कभी माओवादियों के दरभा डिवीजन के लिए सुरक्षित पनाहगाह हुआ करता था, लेकिन नवस्थापित सुरक्षा शिविर ने आक्रामक नक्सल-विरोधी अभियानों, तलाशी अभियानों और निरंतर दबाव को जन्म दिया, जिससे उनकी गतिविधियां कमजोर पड़ गईं। इससे विद्रोहियों का समर्थन नेटवर्क काफी कमजोर हो गया, जिसके कारण ये आत्मसमर्पण हुए और यह क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ का संकेत है। चव्हाण ने शेष माओवादियों से सम्मानजनक जीवन के लिए हिंसा छोड़ने का आग्रह किया। हाल के रुझान गति दर्शाते हैं - 8 जनवरी को पड़ोसी दंतेवाड़ा में 63, 7 जनवरी को सुकमा में और 2025 में पूरे राज्य में 1,500 से अधिक लोगों ने आत्मसमर्पण किया।

कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता को झटका, टीएमसी की याचिका खारिज, ईडी ने कहा-कुछ भी जब्त नहीं किया

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से जुड़े विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। ऐसे में बुधवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने ईडी के इस बयान को रिकॉर्ड किया कि उसने 8 जनवरी को फर्म के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस से कुछ भी जब्त नहीं किया था। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने जो कुछ भी अपने कब्जे में लिया था, उसे सीएम ममता बनर्जी ले गईं। इससे पहले ईडी ने हाई कोर्ट को बताया कि पिछले हफ्ते आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर हुई तलाशी के सिलसिले में दायर याचिकाओं को टाल दिया जाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पार्टी सिर्फ अपने डेटा की सुरक्षा चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय की सुनवाई टालने की अपील पर आपत्ति जताई। दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में मुख्यमंत्री को भी एक पक्ष बनाया है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच के समक्ष कहा कि एजेंसी हाई कोर्ट में मामलों को टालने की मांग कर रही है, क्योंकि उसने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, तो हाई कोर्ट को उस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। इससे पहले इस मामले की सुनवाई तय तारीख पर नहीं हो सकी थी, क्योंकि अदालत परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी। जिसके चलते 9 जनवरी को अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया था।

अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी का बड़ा बयान, परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार 2022 हत्याकांड में अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी।

हाल ही में सामने आई ऑडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पोस्ट्स का जिक्र करते हुए, जिनमें भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को हत्याकांड से जोड़ा गया है, मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उत्तरकाशी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस मामले में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की, जिससे दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिली। हाल ही में कुछ भ्रामक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद, मैंने स्वयं अंकिता के माता-पिता से मुलाकात की और उनके अनुरोध पर, मैंने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का निर्णय लिया। उन्होंने आगे कहा कि मेरी सरकार और मैं शुरू से ही अंकिता के परिवार के साथ खड़े रहे हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके, और हम संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और पहचान की रक्षा के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। इससे पहले 7 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई आरोपियों को दुष्यंत कुमार गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोक दिया था। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला पाया था। उत्तराखंड सरकार ने अंकिता भंडारी के माता-पिता की भावनाओं और बेटी को खोने के बाद उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन्हें ध्यान में रखते हुए 2022 के इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री धामी ने भी दिवंगत अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की थी और उन्हें इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया था।

बीजेपी अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन की ताजपोशी तय, पीएम नरेन्द्र मोदी बनेंगे पहले प्रस्तावक

नई दिल्ली। नितिन नवीन, जिन्हें दिसंबर में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था, 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, सभी राज्य भाजपा अध्यक्षों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दिल्ली में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। भाजपा के मुख्य चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम की घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तीन सेट नामांकन दाखिल किए जाएंगे। एक सेट पर 20 से अधिक निर्वाचित राज्य भाजपा अध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे। दूसरे सेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा के हस्ताक्षर होंगे। तीसरे सेट पर भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। सूत्रों के अनुसार, यदि केवल एक ही नाम नामांकित होता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा उसी दिन कर दी जाएगी। सूत्रों ने आगे बताया कि भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों के संबंध में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, बी.एल. संतोष, सुनील बंसल, अरुण सिंह और तरुण चुग बैठक में उपस्थित हैं। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक 19 और 20 जनवरी को होने वाले भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए है।

भाजपा ने पिछले साल दिसंबर में बिहार के मंत्री और पांच बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था।

संजय राउत का सनसनीखेज आरोप- महायुति खुलेआम बांट रही पैसा

मुंबई।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बुधवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने भाजपा, शिवसेना और एनसीपी समेत महायुति दलों को घर-घर जाकर प्रचार करने के दौरान चंदा बांटने की खुली छूट दे दी है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को आदर्श आचार संहिता लागू होने और आधिकारिक तौर पर चुनाव प्रचार स्थगित होने के बावजूद घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति दी। राउत ने कहा कि कल चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। नियमों, कानूनों और आदर्श आचार संहिता के अनुसार, चुनाव प्रचार आधिकारिक तौर पर कल ही समाप्त हो गया था। लेकिन अचानक महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी आप घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। यह किस तरह का नियम है? यह सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को घर-घर जाकर प्रचार करने के दौरान खुलेआम चंदा बांटने की अनुमति और छूट देता है। राउत ने आगे आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में लगभग 60 लाख, उत्तर प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ और पश्चिम बंगाल में लगभग 54 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम हटाने से चुनाव परिणामों पर असर पड़ सकता है। राउत ने कहा कि देखिए, बिहार में लगभग 60 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से लगभग सवा करोड़ नाम हटाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। और आपने पश्चिम बंगाल के लिए क्या आंकड़ा दिया है-54 लाख एक ही राज्य में 54 लाख मतदाताओं के नाम हटाने से चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। भाजपा पर निष्पक्ष रूप से चुनाव न लड़ने का आरोप लगाते हुए राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू-मुस्लिम नारा विफल हो गया है और अब उसकी जगह प्रवर्तन निदेशालय बनाम तृणमूल कांग्रेस का नारा ले चुका है। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), पुणे नगर निगम (पीएमसी) और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (पीसीएमसी) सहित 29 नगर निगमों के चुनाव होने जा रहे हैं। मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी।